

भारतीय फार्मा क्षेत्र

प्रलिस के लिये:

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (API)।

मेन्स के लिये:

भारत का फार्मा क्षेत्र - संबंधित चुनौतियाँ और कदम जो इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये उठाए जा सकते हैं, मूल्य की दृष्टि से भारत को विश्व की फार्मेसी बनाना।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने [भारतीय फार्मा उद्योग](#) को प्रेरित करने के लिये शैक्षणिक संस्थानों के लिये [फार्मास्युटिकल नवाचार और उद्यमिता](#) पर दिशा-निर्देश जारी किये।

- फार्मास्युटिकल्स विभाग ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और उच्च-स्तर का अनुसंधान करने के लिये राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों के रूप में **मैट्रिय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (NIPERS)** की स्थापना की है।
- यह विभाग जल्द ही 'भारत में फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास व नवाचार को प्रेरित करने की नीति' भी लेकर आ रहा है।

नीति दिशा-निर्देशों का उद्देश्य:

- इन नीति दिशा-निर्देशों का उद्देश्य अकादमिक अनुसंधान को नवीन और व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करना है।
- उद्यमशीलता की गतिविधियों के लिये एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर [आत्मनिर्भर भारत मिशन](#) में योगदान करना।
- फैकल्टी और छात्रों को उद्यमिता के लिये प्रोत्साहित करना।
- संभावित आविष्कारकों और उद्यमियों के लिये प्री-इनक्यूबेशन और सामान्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिये संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
 - बजटीय प्रावधान के अंतर्गत इस संस्थान के लिये वार्षिक बजट के निर्धारित प्रतशित (न्यूनतम 1 प्रतशित) का आवंटन किया जाना चाहिये, ताकि नवाचार और स्टार्टअप से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देकर इनका समर्थन किया जा सके।
 - प्रदान की गई सेवाओं और सुविधाओं के बदले में एक संस्थान स्टार्टअप/स्पनि-ऑफ कंपनी में इक्विटी का एक नश्चित प्रतशित (2 - 9.5%) प्राप्त कर सकता है, जो कर्मचारी के योगदान एवं प्रदान की गई सहायता और संस्थान की बौद्धिक संपदा के उपयोग पर आधारित होता है।
- उद्यमशीलता की पहल का मूल्यांकन नयिमति आधार पर अच्छी तरह से परिभाषित प्रभाव मूल्यांकन मापदंडों जैसे कि **बौद्धिक संपदा** के रूप में दर्ज करना, विकसित उत्पाद और उनका व्यावसायिकरण एवं उत्पन्न रोजगारों की संख्या तथा स्टार्टअप का उपयोग करके किया जाएगा।
- छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिये **उपस्थिति में छूट प्रदान कर** उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिये, भले ही उनकी उपस्थिति 75% से कम हो, ताकि वे उद्यमशीलता की गतिविधियों को भी समय दे सकें और संस्थानों से जुड़े पीएचडी के छात्रों के लिये भी नयिमों में उदारता बरती जानी चाहिये।

भारतीय फार्मा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति:

- भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का **सबसे बड़ा प्रदाता** है। यह विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 50%, अमेरिका में जेनेरिक दवाओं की मांग का 40% और यूके (यूनाइटेड किंगडम) में कुल दवाओं की मांग के 25% की आपूर्ति करता है।
- भारतीय दवा बाजार अनुमानतः 40 अरब अमेरिकी डॉलर का है जबकि दवा कंपनियों 20 अरब अमेरिकी डॉलर की दवाओं का निर्यात करती हैं।
 - हालाँकि यह 1.27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक दवा बाजार का एक छोटा सा हिस्सा है।
- भारत विश्व स्तर पर दवा उत्पादन में मात्रा के हिसाब से तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है।
- भारत की वैश्विक जेनेरिक दवा बाजार में हस्सिदारी 30% से अधिक है लेकिन **नई आणविक इकाई (New Molecular Entity- NME)** में 1% से कम हस्सिदारी है।

- **नई आणविक इकाई (NME)** : एक आदर्श योगिक जिसे पहले मनुष्यों में उपयोग के लिये अनुमोदित नहीं किया गया हो।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2021** के अनुसार, अगले दशक में घरेलू बाज़ार तीन गुना बढ़ने की उम्मीद है।

भारतीय फार्मा क्षेत्र की चुनौतियाँ:

- नवाचार के क्षेत्र में कषमताओं की कमी: भारत जनशक्ति और प्रतभा में समृद्ध है लेकिन फरि भी नवाचार के बुनयादी ढाँचे में पीछे है। सरकार को नवाचार के विकास के लिये अनुसंधान पहल और प्रतभा में नविश करने की आवश्यकता है।
 - सरकार को कुछ नियामक नरिणय लेने में रोग वषियक परीक्षणों और वयक्तपिरकता का समर्थन करना चाहिये।
- बाहरी बाज़ारों का प्रभाव: रपिपोर्ट के अनुसार, भारत सकरयि दवा सामगरी (Active Pharmaceutical Ingredients- API) अन्य देशों पर बहुत अधिक नरिभर है। चीन से 80% API का आयात किया जाता है।
 - अतः भारत आपूर्ति में वयवधान और अप्रत्याशति मूल्य उतार-चढ़ाव पर नरिभर है। आपूर्ति को स्थरि करने एवं बुनयादी ढाँचे के कारयान्वयन के लिये आंतरकि सुवधियों के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है।
- गुणवत्ता अनुपालन जाँच: भारत में वर्ष 2009 के बाद से सबसे अधिक खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food And Drug Administration- FDA) नरिषेक्षण हुए हैं। अतः गुणवत्ता मानकों के उन्नयन हेतु नरितर नविश किये जाने से अन्य क्षेत्रों में विकास और वृद्धि हेतु पूंजी का अभाव के चलते विकास प्रभावति होगा।
- स्थरि मूल्य नरिधारण और नीतगित वातावरण का अभाव: भारत में अप्रत्याशति और लगातार घरेलू मूल्य नरिधारण नीति में बदलाव के कारण चुनौती उत्पन्न हो रही है। इसने नविश एवं नवाचारों के लिये एक अस्पष्ट वातावरण की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

फार्मा क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता:

- दृष्टिकोण बदलने के साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना समय की मांग है। यदि भारत वैश्विक फार्मास्युटिकल क्षेत्र में प्रसंगिक बने रहना चाहता है तो नवाचार को वयवसाय के मूल में अपनाने की आवश्यकता है।
- भारत नवाचार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्य कर रहा है, इससे न केवल देश के विकास में मदद मिलेगी बल्कि स्थायी राजस्व का एक स्रोत भी उपलब्ध होगा जो स्वास्थय संबंधी ज़रूरतों हेतु नए समाधान प्रस्तुत करेगा।
 - इससे भारत में रोग अधिभार में कमी आएगी (तपेदकि और कुषट जैसी भारत-वशिष्ट चिंताओं के लिये दवाओं के विकास पर वैश्विक ध्यान नहीं दिया जाता है), नई उच्च-कुशल नौकरियों का सृजन और संभवतः वर्ष 2030 से लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त नरियात होगा।
 - चीन जैसे देश पहले ही जेनेरिक दवा आधारित विकास को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं।

सरकारी पहलें:

- **फार्मास्युटिकल उद्योग के सुदृढीकरण हेतु योजना:**
 - इस योजना के तहत वतित वर्ष 2021-22 से वतित वर्ष 2025-26 की अवधि के लिये 500 करोड़ रुपए के कुल वतितिय परवियय की घोषणा की गई थी।
- **फार्मास्युटिकल क्षेत्र का पहला वैश्विक नवाचार शखिर सम्मेलन:**
 - नवंबर 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री ने फार्मास्युटिकल क्षेत्र के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिति का उद्घाटन किया, जहाँ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं ने पर्यावरण नियामक, नवाचार के लिये वतितपोषण, उद्योग-अकादमिक सहयोग तथा नवाचार बुनयादी ढाँचे सहित कई वषियों पर वचिार-वमिरश किये।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना:**
 - PLI योजना का उद्देश्य देश में महत्त्वपूर्ण 'की स्टार्टगि मैटेरियल्स' (KSM)/ ड्रग इंटरमीडिएट और सकरयि फार्मास्युटिकल सामगरी (API) के घरेलू वनिरिमाण को बढ़ावा देना है।
- **बल्क ड्रग पार्क योजना को बढ़ावा देना:**
 - सरकार का लक्ष्य देश में थोक दवाओं की नरिमाण लागत और थोक दवाओं के लिये अन्य देशों पर नरिभरता को कम करने हेतु राज्यों के साथ साझेदारी में भारत में 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क वकिसति करना है।

आगे की राह

- भारत में दवा खर्च अगले पाँच वर्षों में 9-12 फीसदी बढ़ने का अनुमान है, जिससे भारत दवा खर्च के मामले में शीर्ष 10 देशों में से एक बन जाएगा।
- आगे बढ़ते हुए घरेलू बकिरी में बेहतर वृद्धि कंपनियों की कषमता पर भी नरिभर करेगी कविे अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को कार्डियोवैस्कुलर, एंटी-डायबटिज़, एंटी-डिसिपेंटेंट और कैंसर वरिधी जैसी बीमारियों के लिये पुरानी चिकित्सा हेतु संरेखति करें।
- भारत सरकार ने लागत में कमी और स्वास्थय देखभाल खर्च को कम करने के लिये कई कदम उठाए हैं। जेनेरिक दवाओं को बाज़ार में तेज़ी से पेश करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है तथा इससे भारतीय दवा कंपनियों को लाभ होने की उम्मीद है।
- इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थय कार्यक्रमों, जीवन रक्षक दवाओं और नविारक टीकों पर ज़ोर देना भी दवा कंपनियों के लिये अच्छा संकेत है।

स्रोत: पी.आई.बी.

